PRGI : APHIN/26/A3657

पेन पॉवर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 1 अंक - 31 मंगलवार, अगस्त 11, 2026 विशाखापट्टनम संपादक: गंट्यादा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

राउडी तत्वों और गांजा गिरोहों को कुचलेंगे: सीएम चंद्रबाबू

(पेन पॉवर न्यूज): एलुरु जिला, 10 अगस्त: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर काम करने से आंध्र प्रदेश 'डबल इंजन की रफ्तार' से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने एलुरु जिले के कलिदिंडी में 'मी भूमि दृ मी हक्कु' (आपकी जमीन दृ आपका अधिकार) कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को पट्टादार पासबुक वितरित कीं। इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता में दिख रहा उत्साह इस बात का संकेत है कि जब भी चुनाव होंगे, एनडीए की ही जीत होगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को दिए गए भूमि पट्टों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन जमीनों से जुड़ी पुरानी समस्याओं का अब समाधान कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में जनता की समस्याओं का समाधान करने से बड़ी संतुष्टि उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को दी जा रही पट्टादार पासबुक पर किसी को भी अपनी तस्वीर लगाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के शासनकाल में जब लोगों ने अपनी जमीनें देने से इनकार किया, तो उन जमीनों को धारा 22–ए के तहत डालकर उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याओं का समाधान करने पर जनता सरकार की सराहना करेगी।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जनता ने देख लिया है कि जब किसी पार्टी ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 151 सीटें जीतने वाली पार्टी का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा कि वह भी बटन दबाकर, पर्दों के पीछे से आकर, विमान से यात्रा कर वापस जा सकते हैं, लेकिन वह वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की तरह शासन नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा?

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य के 7,700 गांवों में 32.32 लाख पट्टादार पासबुक वितरित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये पासबुक ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर तैयार की गई हैं, इसलिए इनमें दर्ज विवरण को कोई बदल नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि 9,365 गांवों में 68.64 लाख पट्टादार पासबुक वितरित की जानी हैं। अधिकारियों को अगले सात महीनों में यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

"राउडी तत्वों और गांजा गिरोहों को कुचल देंगे," मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चेतावनी दी।

पट्टादार पासबुक वितरण सम्मान से जुड़ा कार्यक्रम

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पट्टादार पासबुक का वितरण एक सम्मानजनक कार्यक्रम है और यह प्रत्येक व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ लोगों को भूमि दस्तावेज वितरित करते समय भ्रष्टाचार की संभावना को रोकने के लिए इन्हें ग्राम सभाओं के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

उन्होंने लोगों से पारिवारिक विवादों को कम करने और जमीन से जुड़े मामलों में मुकदमेबाजी से बचने की अपील की।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का पद उनके लिए नया नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब वह पहले से अधिक तेजी से काम कर रहे हैं और तकनीक भी काफी आगे बढ़ चुकी है।

उन्होंने कहा कि एलुरु जिले में जहां भी देखें, मछली पालन के तालाब दिखाई देते हैं, लेकिन पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कैकलुरु में पेयजल संकट दूर करने के लिए 36 करोड़ मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुपर सिक्स के वादों को लागू किया है और लोगों को गड्ढों से मुक्त सड़कों पर सुगम यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य पहले ही कठिन परिस्थितियों को पार कर आगे बढ़ रहा है।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया में खान–पान की आदतें बदल रही हैं और उन्होंने दोहराया कि भविष्य एक्वाकल्चर क्षेत्र का है। उन्होंने बताया कि एक्वाकल्चर क्षेत्र को सहायता देने के लिए उनकी सरकार ने ध1.50 प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने एक्वा और नॉन–एक्वा जोन के नाम पर एक्वाकल्चर क्षेत्र को परेशान किया।

bl thvk dk Q,pl;u bfM;k d y[k l dkbl lc/k ugh% vk/k çn'k ljdkj dh lQkbl

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 10 अगस्त: आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंत्री नारा लोकेश पर फॉर्च्यून इंडिया में लेख प्रकाशित कराने के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक सरकारी धन खर्च किए जाने का दावा पूरी तरह गलत है। सरकार ने लोकेश के खिलाफ किए जा रहे गलत प्रचार का खंडन किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जीओ का फॉर्च्यून इंडिया के लेख से कोई संबंध नहीं है।

सरकार ने बताया कि 18 जनवरी 2025 को जारी किया गया जीओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (ॅम्थ) 2025 में आंध्र प्रदेश में निवेश के अवसरों के प्रचार–प्रसार से संबंधित था। इस जीओ में एक अंग्रेजी समाचार चौनल को प्रचार संबंधी गतिविधियों के लिए भुगतान करने के सरकारी निर्देश दिए गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्च्यून इंडिया और CNBC TV दो अलग–अलग संस्थाएं हैं और दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है।

सरकार ने आरोप लगाया कि जीओ को तोड़–मरोड़कर मंत्री नारा लोकेश के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। सरकार ने चेतावनी दी कि जनता को जानबूझकर गलत जानकारी देना अपराध है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आंध्र प्रदेश में प्रमुख अधिकारियों के तबादलों पर रोक बढ़ाई गई

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 10 अगस्त: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रमुख अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। सरकार ने यह निर्णय मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के मद्देनजर लिया है। सरकार ने प्रमुख सरकारी अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर लगी रोक को 3 अक्टूबर तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही SIR प्रक्रिया पूरी होने तक प्रमुख अधिकारियों के तबादलों पर रोक जारी रहेगी।

आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम संशोधित किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 28 सितंबर तक जारी रहेगी। 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक को बढ़ा दिया है। इस निर्णय के अनुसार, मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े प्रमुख अधिकारी 3 अक्टूबर तक अपने मौजूदा पदों पर बने रहेंगे। इस संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से G-O-Rt-No-1545 जारी किया गया है।

तंबाकू किसानों के लिए खुशखबरी: 50 हजार का ब्याज–मुक्त ऋण

(पेन पॉवर न्यूज): गुंटूर जिला, 10 अगस्त: आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजरापु अच्चेन्नायडू ने घोषणा की कि प्रत्येक तंबाकू किसान को 50 हजार का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि दो वर्षों तक बिना ब्याज के दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की ओर से तंबाकू किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 की सहायता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि तंबाकू की खरीद के नौ दिनों के भीतर किसानों के बैंक खातों में राशि जमा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष तंबाकू की खेती को 80 मिलियन किलोग्राम तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

अच्चेन्नायडू ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और "कुल्हाड़ी वाली पार्टी" के प्रमुख पर अनावश्यक आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए आलोचना की।

मंत्री अच्चेन्नायडू ने सोमवार को गुंटूर जिले स्थित टोबैको बोर्ड कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में तंबाकू किसानों की समस्याओं, कीमतों और तंबाकू खरीद की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

बैठक में मंत्री गोट्टिपाटि रवि कुमार, डोला बाल वीरांजनयुलु, प्रकाशम जिले के विधायक, टोबैको बोर्ड के अधिकारी और किसान शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए और बाद में बैठक को संबोधित किया।

जगन के शासन में तंबाकू की कीमतें घटीं, फिर भी कुछ नहीं किया: अच्चेन्नायडू

कृषि मंत्री अच्चेन्नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान तंबाकू की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जगन के शासनकाल में मार्कफेड (MARKFED) के माध्यम से केवल 11 मिलियन किलोग्राम तंबाकू की खरीद की गई थी। उन्होंने कहा कि नारा चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में रहने के दौरान ही तंबाकू किसानों को लाभ मिला। उन्होंने किसानों से इस बात को याद रखने और तथ्यों को समझने की अपील की।

मंत्री ने बताया कि तंबाकू की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारी कम ग्रेड का हवाला देकर मनमाने तरीके से किसानों के साथ व्यवहार नहीं कर सकेंगे।

बाकी पात्र बुनकरों को भी 'नेतन्नला सेव लो' योजना के तहत आर्थिक सहायता: मंत्री सविता

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 10 अगस्त: मंत्री सविता ने बताया कि मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के हाथों हाल ही में 'नेतन्नला सेव लो' (बुनकरों की सेवा में) योजना की शुरुआत की गई है। सोमवार को मंत्री ने राज्य सचिवालय में इस योजना की समीक्षा बैठक की।

इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से अब तक छूट गए सभी पात्र बुनकरों की पहचान कर प्रत्येक को ध25 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री सविता ने कहा कि अब तक 71,536 बुनकरों को ध25 हजार की दर से आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी बाकी रह गए पात्र बुनकरों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि 13,678 बुनकरों ने 'नेतन्नला सेव लो' योजना के लिए आवेदन किया है। इनमें से पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें 'नेतन्नला नेस्तम' योजना का लाभ दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि बाकी पात्र लाभार्थियों को भी एक सप्ताह के भीतर ध25 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि बुनकरों को आर्थिक लाभ पहुंचाना मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 85,678 हथकरघा बुनकरों को एनटीआर भरोसा पेंशन दी जा रही है। मंत्री सविता ने बताया कि 62,541 बुनकर परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इस समीक्षा बैठक में हथकरघा एवं वस्त्र विभाग की आयुक्त रेखा रानी और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

वाईएसआरसीपी नेता चिंताडा रवि कुमार पर कसता शिकंजा

श्रीकाकुलम, 10 अगस्त: महिला एसआई के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में वाईएसआरसीपी नेता चिंटाडा रवि कुमार फिलहाल रिमांड पर हैं। घटना के नौ दिन बाद पुलिस ने रवि कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के हालिया श्रीकाकुलम दौरे के दौरान रवि कुमार ने एक महिला एसआई के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। गिरफ्तारी के डर से रवि कुमार कथित तौर पर फरार हो गए थे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पता लगाया है कि करीब नौ दिनों के दौरान उन्होंने आठ अलग–अलग स्थानों पर ठिकाने बदले। पुलिस के अनुसार, इस दौरान उन्होंने 24 सिम कार्ड और 21 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कथित तौर पर विजयनगरम, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, ओडिशा और अराकू में ठिकाने बनाए। अराकू से कार से श्रीकाकुलम की ओर आते समय टास्क फोर्स पुलिस ने उन्हें एच्चेरला मंडल के चिलकापालेम के पास हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनसे पूछा कि वह फरार क्यों हुए थे। इस पर रवि कुमार ने कथित तौर पर जवाब दिया कि वह घर पर ही थे। हालांकि, पुलिस ने जब उनके फरार होने से जुड़े वीडियो और अन्य सबूत दिखाए, तो रवि कुमार कथित तौर पर चुप हो गए।

लंदन में मंत्री नारायण की टीम, अमरावती की प्रतिष्ठित इमारतों के डिजाइनों पर अहम चर्चा

लंदन/अमरावती, 10 अगस्त: आंध्र प्रदेश के मंत्री पी. नारायण और उनकी टीम का लंदन दौरा जारी है। अमरावती में निर्माणाधीन प्रतिष्ठित इमारतों के अंतिम डिजाइनों पर चर्चा करने के लिए मंत्री नारायण लंदन पहुंचे हैं।

मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी आधिकारिक दौरे के तहत रविवार रात लंदन पहुंचे। इस दौरान नारायण विधानसभा, हाईकोर्ट और सचिवालय टावरों के बाहरी डिजाइनों को लेकर आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंसी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित इमारतों के डिजाइन और कंसल्टेंसी से जुड़ी नॉर्मन फोस्टर एंड पार्टनर्स, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ब्यूरो हैपोल्ड कंसल्टेंसी और एलएंडटी के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठकों में मंत्री नारायण शामिल होंगे।

विधानसभा भवन के ऊपर बनने वाले टावर के डिजाइन पर फोकस

बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा भवन के ऊपर प्रस्तावित ऊंचे टावर के डिजाइन पर चर्चा की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार इस टावर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, जहां से पर्यटक ऊंचाई से अमरावती राजधानी क्षेत्र का विहंगम दृश्य देख सकेंगे।

मंत्री नारायण आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंसी प्रतिनिधियों के साथ वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति तथा भविष्य में प्रतिष्ठित इमारतों के निर्माण की प्रक्रिया पर भी चर्चा करेंगे। मंत्री नारायण के साथ सीआरडीए आयुक्त विजयारामराजू, अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक कुमार और मुख्य अभियंता भी लंदन गए हैं।

संपादकीय

क्या विरोध प्रदर्शनों का दमन ही समाधान है?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली हथियार विरोध प्रदर्शन है। मतदान करने के बाद भी लोगों को अपनी असंतुष्टि, पीड़ा और मांगों को सरकार के सामने रखने का संवैधानिक अधिकार है और शांतिपूर्ण आंदोलन इसका एक लोकतांत्रिक माध्यम है। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो सत्ता में चाहे कोई भी सरकार रही हो, एक समान प्रवृत्ति दिखाई देती है। वह यह कि विरोध प्रदर्शनों को सुनने के बजाय उन्हें समय बीतने के साथ कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन अक्सर यह मानकर चलता है कि अंततः आंदोलन थक जाएगा, लोग बिखर जाएंगे और नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन और कॉकरोच जनता पार्टी (ब्भ्च्) के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलनों के संदर्भ में यह मुद्दा एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बना है।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विरोध प्रदर्शनों का सामना करने वाली सरकारों के रवैये में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के लिए आगे आने के बजाय उन्हें कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक नियंत्रण के जरिए संभालने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। मणिपुर की इरॉम शर्मिला ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (।थ्ब्।) को समाप्त करने की मांग को लेकर 16 वर्षों तक अनशन किया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय गिरफ्तारी और जबरन भोजन कराने जैसे कदमों के जरिए आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। आज लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के संदर्भ में भी सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। क्या लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल असहमति को दबाना है? या फिर उसे जनता से संवाद करना चाहिए, उनकी चिंताओं को समझना चाहिए और समाधान के रास्ते तलाशने चाहिए? यह बुनियादी सवाल एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। हालिया घटनाक्रम एक बार फिर यह याद दिलाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बल प्रयोग से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, संवाद और संवैधानिक चर्चा के माध्यम से मजबूत होती है। सरकार के लिए कानून–व्यवस्था और शांति बनाए रखना जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान करना भी उसकी जिम्मेदारी है। जब इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ता है, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। आंदोलनों को बल प्रयोग से दबाने से भले ही अस्थायी परिणाम मिल जाएं, लेकिन इससे लोगों के मन में असंतोष और बढ़ सकता है। भारत का किसान आंदोलन इसका एक बड़ा उदाहरण है। शुरुआत में केंद्र सरकार ने आंदोलन को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। समय के साथ आंदोलन मजबूत होता गया। एक वर्ष तक चले आंदोलन के बाद अंततः सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े। यानी इतिहास बताता है कि लोकतंत्र में लंबे समय तक चलने वाले शांतिपूर्ण आंदोलनों का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या हर विरोध प्रदर्शन उचित है? क्या सरकार को हर मांग तुरंत स्वीकार कर लेनी चाहिए? ये भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। लोकतंत्र में सरकार को जनता की राय सुननी चाहिए। साथ ही नीतिगत फैसले कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लिए जाने चाहिए। इसलिए संवाद ही सही रास्ता हैकृन तो उपेक्षा और न ही दमन। वर्तमान घटनाक्रम में सोशल मीडिया का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहले कोई आंदोलन मुख्य रूप से स्थानीय स्तर तक सीमित रहता था। अब वह कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल सकता है। वीडियो, लाइव प्रसारण और जनता की प्रतिक्रियाएं आंदोलनों को नई ताकत देती हैं। इसलिए केवल पुलिस कार्रवाई के जरिए किसी आंदोलन को रोकना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है।

सरकारें आमतौर पर यह रणनीति अपनाती हैं कि 'समय बीतने के साथ आंदोलन शांत हो जाएगा।' लेकिन यह रणनीति हमेशा काम नहीं करती। यदि जनता की समस्या वास्तविक है और नेतृत्व विश्वसनीय है, तो आंदोलन और मजबूत हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र में संवाद, परामर्श और पारदर्शिता बेहद आवश्यक हैं। इस मामले में विपक्ष की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। जनसमस्याओं को राजनीतिक लाभ–हानि के नजरिए से देखने के बजाय उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। विरोध प्रदर्शनों को केवल सरकार विरोधी प्रचार का मंच बना देना भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसी तरह सरकार द्वारा हर आलोचना को देशद्रोह या विदेशी साजिश के रूप में पेश करना भी लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए नुकसानदायक है। इरॉम शर्मिला से लेकर सोनम वांगचुक तक के हर आंदोलन का संदेश एक ही हैकृसत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता की आकांक्षाएं स्थायी होती हैं। विरोध प्रदर्शनों को दबाने से समस्याएं समाप्त नहीं होतीं। जनता की बात सुनने, उसकी चिंताओं को समझने और समाधान देने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है।

समान अवसर सामाजिक प्रगति की नींव हैं

बेटे और बेटियां ही परिवार की सच्ची संपत्ति हैं

बच्चे के विकास में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है

प्यार और विश्वास उनके भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं

परिवार के रिश्तों को नया अर्थ देने वाला विशेष दिन

बेटे और बेटियां हर परिवार के सच्चे अनमोल रत्न होते हैं। वे न केवल घर में खुशियां लाते हैं, बल्कि परिवार की आकांक्षाओं, मूल्यों और परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की हंसी से घर खुशियों से भर जाता है, जबकि उनकी उपलब्धियां माता–पिता के लिए गर्व का विषय बनती हैं। इसलिए ''सन्स एंड डॉटर्स डे (Sons and Daughters Day)'' हर वर्ष बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह और जिम्मेदारियों को पहचानने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें परिवार के रिश्तों के महत्व और उनकी महानता की याद दिलाता है।

आज की आधुनिक जीवनशैली में माता–पिता नौकरी, व्यवसाय और अन्य जिम्मेदारियों में तेजी से व्यस्त होते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बच्चों के साथ बिताने वाला समय धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि, बच्चों को महंगे उपहार और भौतिक सुख–सुविधाएं देने की बजाय उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना कहीं अधिक मूल्यवान है। जब बच्चों को अपने माता–पिता से खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलता है, तो वे अपने विचारों और भावनाओं को सहजता से साझा कर पाते हैं। इससे परिवार के सदस्यों को बच्चों के विचारों, जरूरतों और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

बचपन वह मजबूत नींव है, जिस पर व्यक्ति का भविष्य निर्मित होता है। इस अवस्था में बच्चे जिन मूल्यों और आदतों को सीखते हैं, वे उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईमानदारी, अनुशासन, जिम्मेदारी और मानवता जैसे गुणों की शुरुआत घर से ही होती है। माता–पिता का व्यवहार बच्चों के लिए पहला पाठ होता है। इसलिए घर में स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और सहयोगपूर्ण वातावरण बनाना बेहद आवश्यक है।

आज के दौर में तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और बच्चे मोबाइल फोन, कंप्यूटर तथा सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने लगे हैं। एक सीमा तक तकनीक लाभदायक हो सकती है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग परिवार के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष संवाद को कम कर सकता है। साथ मिलकर भोजन करना, खेल खेलना, किताबें पढ़ना और पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेना रिश्तों को मजबूत कर सकता है। ऐसे छोटे–छोटे प्रयास बच्चों के भावनात्मक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

एक समय था जब कई क्षेत्रों में बेटों और बेटियों के साथ अलग–अलग व्यवहार किया जाता था। विशेष रूप से लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि, आज परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं और उत्कृष्ट पदों तक पहुंच रही हैं। समाज भी तेजी से यह स्वीकार कर रहा है कि जब बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं, तो वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर सकते हैं।

हर बच्चे की सफलता के पीछे माता–पिता का प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेल, कला, विज्ञान, तकनीक और उनकी रुचि के अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनकी छोटी–छोटी उपलब्धियों की सराहना करने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। साथ ही, माता–पिता को बच्चों की असफलताओं को भी समझना चाहिए और उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने के लिए आवश्यक साहस एवं सहयोग देना चाहिए।

आज के समाज में बच्चे बढ़ते मानसिक और भावनात्मक दबाव का भी सामना कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ने का दबाव, पढ़ाई का बोझ और सोशल मीडिया का प्रभाव उनके भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में माता–पिता को बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और उन्हें भावनात्मक सहारा देना चाहिए। नियमित बातचीत और उनकी भावनाओं को समझने से कई समस्याओं की पहचान शुरुआती स्तर पर ही की जा सकती है और उन्हें गंभीर होने से रोका जा सकता है।

बच्चों को अच्छी शिक्षा देना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अच्छे संस्कार और चरित्र प्रदान करना भी उतना ही आवश्यक है। सामाजिक जिम्मेदारी की भावना, बड़ों का सम्मान, प्रकृति के प्रति प्रेम और सहनशीलता जैसे गुण उनके व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से आकार देने में मदद करते हैं। शैक्षणिक ज्ञान के साथ–साथ जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा बच्चों को जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनने में मदद करती है।

बेटे और बेटियां केवल अपने परिवार का भविष्य ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य के प्रतिनिधि भी हैं। आज के बच्चे ही कल के डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, नेता, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर बनेंगे। इसलिए उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना परिवार, समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है। बच्चों का कल्याण और विकास राष्ट्र की प्रगति की मजबूत नींव तैयार करता है।

''सन्स एंड डॉटर्स डे'' को केवल एक दिन के उत्सव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे परिवार के रिश्तों को मजबूत करने और माता–पिता तथा बच्चों के बीच के संबंधों को और गहरा करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चों के साथ बिताया गया हर पल अनमोल समझा जाना चाहिए। जो बच्चे प्यार, विश्वास, प्रोत्साहन और आपसी सम्मान से भरे वातावरण में बड़े होते हैं, उनके जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनने की संभावना अधिक होती है। इसलिए माता–पिता के लिए केवल अपने बच्चों से प्यार करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने बच्चों को समझना, उनकी बातें सुनना, उनके सपनों का सम्मान करना और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में उनका साथ देना चाहिए।

हर बच्चेकृचाहे वह बेटा हो या बेटीकृको समान अवसर देने वाला पोषणपूर्ण वातावरण तैयार करना केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

पाकिस्तान की कश्मीर 'कहानी' अब अपने ही विरोधाभासों के बोझ तले ढह रही

पाकिस्तान के केंद्रीय विमर्श ने कश्मीर विवाद को मूल रूप से आत्मनिर्णय के अधिकार की भाषा में पेश किया और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। हालांकि, पिछले दो महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों ने एक असहज विरोधाभास को उजागर कर दिया है। जुलाई की शुरुआत में बढ़ी हुई कीमतों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नागरिक समाज के सरकार–विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ यह विरोध अगस्त की शुरुआत तक कई सप्ताह के इंटरनेट बंद, राज्य की कार्रवाई में दर्जनों लोगों की मौत, एक राजनीतिक गठबंधन पर प्रतिबंध और त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में बदल गया है।

सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के साथ स्थिति तेजी से हिंसक हो गई। यह हिंसा उस समय हुई जब जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त की शुरुआत तक तीन चरणों में स्थानीय चुनाव कराए जा रहे थे। वास्तव में, 9 जून को एक ब्रिटिश नागरिक, जो इन प्रदर्शनों में शामिल भी नहीं था, एक भटकी हुई गोली की चपेट में आकर मारा गया था, हालांकि उसकी मौत की खबर अब सामने आई है।

1974 के अंतरिम संविधान ने च्वज्ञ के राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा तैयार की, साथ ही इस क्षेत्र पर इस्लामाबाद के नियंत्रण को संस्थागत रूप दिया। 2018 के संवैधानिक सुधारों के तहत क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ वित्तीय और विधायी अधिकार दिए गए, लेकिन इस्लामाबाद ने कश्मीर मामलों के मंत्रालय, वित्तीय निर्भरता और निगरानी तंत्र के माध्यम से अपना पर्याप्त प्रभाव बनाए रखा।

JAAC और आरक्षित सीटों का विवाद

वर्तमान आंदोलन के केंद्र में ''जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है। यह व्यापारियों, वकीलों, छात्रों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का गठबंधन है। यह गठबंधन पहली बार 2023 में आटा सब्सिडी, बिजली दरों और बढ़ती जीवन–यापन लागत जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर मजबूत हुआ था। इन अभियानों के परिणामस्वरूप 2024 और 2025 में सरकार को कुछ रियायतें देनी पड़ीं।

हालांकि, इसके बाद JAAC ने अपनी मांगों को बढ़ाकर 38 सूत्रीय चार्टर में बदल दिया। इसका केंद्रीय मुद्दा च्वज्ञ की 45 सदस्यीय विधानसभा में जम्मू–कश्मीर के पाकिस्तान के मुख्य भूभाग में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें हैं। श्र।।ब लंबे समय से तर्क देती रही है कि इस व्यवस्था के कारण इस्लामाबाद, जिसका इस क्षेत्र में कोई स्थानीय हित नहीं है, क्षेत्र के धन को दूसरी दिशा में मोड़ने में सक्षम हुआ है।

पाकिस्तानी सरकार के लिए यह विवाद कश्मीर पर उसके व्यापक कूटनीतिक रुख से जुड़ा हुआ है। भारत के अपने संवैधानिक दावों के अनुरूप, जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 14(4) के तहत भारत ने नियंत्रण रेखा के पार स्थित क्षेत्रों के लिए 114 में से 24 सीटें आरक्षित रखी हैं। इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव से कई नए सवाल खड़े हो सकते हैं और यह संकेत मिल सकता है कि कश्मीर की स्थिति को लेकर पाकिस्तान की संवैधानिक समझ में बदलाव हो रहा है।

JAAC और पाकिस्तानी सरकार के बीच बातचीत मई में विफल हो गई। इसके बाद इस्लामाबाद ने 5 जून को आतंकवाद–रोधी कानूनों के तहत संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब से दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 1974 के अंतरिम संविधान के तहत PoK में अर्ध–स्वायत्त व्यवस्था है, जिसमें अपनी विधानसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं। हालांकि, इन पदों पर रहने वाले उम्मीदवारों के लिए पाकिस्तानी राज्य के प्रति वफादारी बनाए रखना अनिवार्य है। इससे वहां स्वीकार्य राजनीतिक गतिविधियों का दायरा सीमित हो जाता है।

जुलाई में JAAC ने कथित तौर पर सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पत्र लिखा। संभवतः उसे यह पता था कि राज्य में वास्तविक सत्ता किसी नागरिक संस्था के बजाय रावलपिंडी के पास है। इसके बाद राज्य की प्रतिक्रिया सुरक्षा–केंद्रित हो गई। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख और कठोर कार्रवाई ने पहले से मौजूद सरकार–विरोधी असंतोष को और गहरा कर दिया।

कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का राजनीतिक विमर्श भले ही अलगाववाद की भाषा में रहा हो, लेकिन मौजूदा आंदोलन में अलगाववादी भावना दिखाई नहीं दी है। इसके बजाय आंदोलन ने खराब शासन, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन, वित्तीय पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासन में जवाबदेही जैसे मुद्दों पर जोर दिया है।

इसलिए पाकिस्तान के कश्मीर विमर्श पर सबसे बड़ा दबाव नई दिल्ली से नहीं, बल्कि उसके अपने शासन की विफलताओं से पैदा हो रहा है। हालिया घटनाक्रम को समझने के लिए यह तथ्य बेहद महत्वपूर्ण है।

सूचना पर नियंत्रण

विदेशी मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध पाकिस्तान के सीमावर्ती और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रोंकृ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और PoK's प्रति उसके दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं, जहां सूचना पर कड़ा नियंत्रण प्रशासन की महत्वपूर्ण रणनीति माना जाता है।

अगस्त की शुरुआत में पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने Foreign Media Facilitation Guidelines, 2026 जारी किए। इनके तहत सभी पत्रकारों के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर काम करने हेतु मंत्रालय के बाह्य प्रचार प्रभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया गया है। ये नियम फ्रीलांस पत्रकारों, अनुवादकों, फिक्सरों और स्थानीय सहयोगियों पर भी लागू होते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता के आधार पर मान्यता निलंबित करने की चेतावनी भी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करने वाले विदेशी संवाददाताओं को पहले भी नौकरशाही संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता रहा है और उनके NOC में देरी की जाती रही है या उन्हें रोक दिया जाता है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन अक्सर रिपोर्टिंग के लिए स्थानीय पत्रकारों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब स्थानीय पत्रकार भी इस नए नियामक ढांचे के दायरे में आ गए हैं।

मुजफ्फराबाद में मतदान केंद्रों से रिपोर्टिंग करने के आरोप में एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी 'पीत पत्रकारिता' (yellow journalism) में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मीडिया सेंसरशिप लागू की गई। पाकिस्तान में मीडिया का माहौल इतना गंभीर हो गया है कि देशभर के पत्रकारों को सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ तय 'रेड लाइन्स' पार करने पर 'उठा लिए जाने' यानी जबरन गायब किए जाने का खतरा बना रहता है। पाकिस्तान का कश्मीर संबंधी मामला इस नैतिक दावे पर आधारित रहा है कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित किया गया है। यह दावा अक्सर जम्मू–कश्मीर में भारत की नीतियों को लेकर किया जाता रहा है, विशेष रूप से 2019 में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद।

लेकिन PoK में उभरता वर्तमान माहौल उन्हीं आरोपों की छाया प्रस्तुत करता दिखाई दे रहा हैकृएक प्रतिबंधित गठबंधन, लंबे समय तक आंतरिक बंदी जैसी स्थिति, सुरक्षा–केंद्रित प्रशासन और पाकिस्तान द्वारा प्रशासित कश्मीर के उस हिस्से में एक ऐसे आंदोलन के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जो क्षेत्र की स्थिति को चुनौती भी नहीं दे रहा है।

इसके राजनीतिक और प्रतिष्ठित नुकसान केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब वह पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खुद को एक जिम्मेदार कूटनीतिक शक्ति के रूप में पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहा है।

एचआईवीध्एड्स मुक्त समाज के निर्माण में सभी भागीदार बनें: कलेक्टर

काकीनाडा, 10 अगस्त (पेन पावर): काकीनाडा जिला कलेक्टर एम.एन. हरेन्धिर प्रसाद ने युवाओं, छात्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जनता से एचआईवीध्एड्स मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। सोमवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर अपूर्वा भारत और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एचआईवीध्एड्स जागरूकता पोस्टर का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि जिले में 12 अगस्त से 45 दिनों तक गहन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत एलईडी स्क्रीन वाले वाहनों से प्रचार, जागरूकता कार्यक्रम और घर–घर सर्वेक्षण किए जाएंगे। 300 गांवों में जागरूकता बैठकें और रैलियां आयोजित की जाएंगी। वहीं 471 हाई स्कूलों और 107 जूनियर कॉलेजों में रेड रिबन क्लबों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 9,000 घरों में जनजागरूकता अभियान, 5 किलोमीटर रेड रन मैराथन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं और पांच विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। करीब 45,000 जोखिम आकलन सर्वेक्षण भी किए जाएंगे। कलेक्टर ने लोगों से एचआईवीध्एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने, बचाव के उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

कलेक्टर और एसपी ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का निरीक्षण किया

गुंटूर, 10 अगस्त (पेन पावर): जिला कलेक्टर सी. एम. साईकांत वर्मा ने सोमवार को राजधानी परेड ग्राउंड में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने 13 अगस्त को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, न्यायिक अधिकारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के आने–जाने के मार्गों तथा उनके लिए निर्धारित स्थानों का भी निरीक्षण किया।

समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय

जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पार्किंग और यातायात को ध्यान में रखते हुए प्रभावी यातायात योजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया। सरकारी विभागों को अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली झांकियों की तैयारियां पूरी करने और 13 अगस्त की अंतिम रिहर्सल में उनका प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एसपी वकुल जिंदल, सीआरडीए के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम आयुक्त के. मयूर अशोक, संयुक्त कलेक्टर आशुतोष श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी निरीक्षण में शामिल हुए।

मच्छरों के नियंत्रण के लिए कड़े कदम: काकीनाडा कलेक्टर

काकीनाडा, 10 अगस्त (पेन पावर): काकीनाडा जिला कलेक्टर एम.एन. हरेन्धिर प्रसाद ने कहा कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपने आसपास बारिश का पानी और गंदा पानी जमा नहीं होने देने की अपील की। मच्छर नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को काकीनाडा के कुळाईचेरुवु पार्क में पानी में गंबूसिया मछली के बच्चे छोड़े गए। कलेक्टर एम.एन. हरेन्धिार प्रसाद और जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के. अनिता ने कार्यक्रम में भाग लेकर मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ा। कलेक्टर ने बताया कि गंबूसिया मछलियां पानी में मौजूद मच्छरों के लार्वा को खाकर उनके प्रजनन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। जिले में पुराने कुओं,

अनुपयोगी तालाबों और स्थायी जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां लगातार गंबूसिया मछलियां छोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान मच्छरों के प्रकोप को कम करने और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष एंटी–लार्वा अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। कलेक्टर ने मच्छर नियंत्रण में जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों से अपने आसपास पानी जमा न होने देने और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, मत्स्य एवं नगर पालिका विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का समाधान करें: कलेक्टर पी. राजा बाबू

ओंगोल, 10 अगस्त (पेन पावर): जिला कलेक्टर पी. राजा बाबू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोमवार को ओंगोल स्थित कलेक्ट्रेट के 'जनसमस्या समाधान मंच' में आयोजित 'मीकोसम' कार्यक्रम में कलेक्टर ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से शिकायतें प्राप्त कीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित एवं प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या तत्काल कम करने तथा प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक पढ़कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश

दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को संतोषजनक और स्थायी समाधान मिले, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के बाद सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर जनता से सीधे सुझाव और प्रतिक्रिया ली जाएगी तथा इस संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कुल 286 शिकायतें प्राप्त हुईं। संयुक्त कलेक्टर कल्पना कुमारी, जिला राजस्व अधिकारी वेंकटरमण सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान पुलिस का लक्ष्य: प्रकाशम एसपी

ओंगोल, 10 अगस्त (पेन पावर): प्रकाशम जिला एसपी वी. हर्षवर्धन राजू ने सोमवार को अडांकी पुलिस स्टेशन परिसर में 'मीकोसम' जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से 64 शिकायतें प्राप्त कीं।

अधिकांश शिकायतें पारिवारिक विवाद, ससुराल पक्ष की प्रताड़ना तथा भूमि और संपत्ति विवादों से संबंधित थीं। एसपी ने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत की पारदर्शी जांच कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके बाद एसपी ने दर्शी उप–विभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण और कानून–व्यवस्था की समीक्षा की। लंबित मामलों और गैर–जमानती वारंटों का शीघ्र निपटारा करने, चोरी की संपत्ति बरामद करने और ड्रोन के माध्यम से असामाजिक

गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, गांजा एवं मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई तथा पुराने अपराधियों पर निगरानी रखने को कहा। साथ ही साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और कानूनों के प्रति जनता में लगातार जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के अंत में एसपी ने अडांकी पुलिस स्टेशन परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

वेलिगोंडा परियोजना के विस्थापितों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

मार्कापुरम, 10 अगस्त (पेन पावर): वेलिगोंडा परियोजना के विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को मार्कापुरम जिला कलेक्ट्रेट में तनाव की स्थिति बन गई। परियोजना से प्रभावित गांवों के सैकड़ों विस्थापित कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।

विस्थापितों ने मांग की कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवाओं को आर एंड आर पैकेज और उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया।

उन्होंने सभी पात्र विस्थापितों को मुआवजा और पुनर्वास लाभ देने तथा समस्याओं का समाधान होने तक उन्हें अपने घर

खाली करने के लिए मजबूर नहीं करने की मांग की। साथ ही समाधान के बाद कम से कम तीन महीने का समय देने की मांग की और अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान विधायक कंदुला नारायण रेड्डी और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। विधायक ने विस्थापितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।

एनटीआर जिले में विशेष आधार सेवा शिविर

विजयवाड़ा, 10 अगस्त (पेन पावर): एनटीआर जिला कलेक्टर डॉ. जी. लक्ष्मीश ने बताया कि लोगों को आसान और तेज आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले में विशेष आधार सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 11 से 14 अगस्त तथा 17 से 29 अगस्त तक चयनित स्वर्ण ग्राम एवं स्वर्ण वार्ड कार्यालयों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित होंगे। शिविरों में नए आधार पंजीकरण के साथ नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक विवरण अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने की सलाह दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को दूर जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए नजदीकी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ही आधार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने लोगों से विशेष शिविरों का लाभ उठाने और आवश्यक आधार विवरण अपडेट कराने की अपील की। अधिकारियों को शिविरों में पर्याप्त सुविधाएं और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

"पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग" अभियान में नागरिकों की भागीदारी जरूरी

रामपचोडवरम, पेन पावर, 10 अगस्त: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पोलवरम जिला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने अधिकारियों को 10 से 15 अगस्त तक "पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग" और "देश के लिए... अने नेनु" अभियान को व्यापक स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, युवाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, कलाकारों और स्वयंसेवी संस्थाओं से 30 सेकंड का वीडियो बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की।

कलेक्टर ने 13 से 15 अगस्त तक "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम आयोजित करने, 14 अगस्त को पौधारोपण कार्यक्रम चलाने तथा 14 और 15 अगस्त को सरकारी भवनों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को तिरंगे की रोशनी से सजाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।

जनसमस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता: कलेक्टर विजया सुनीथा

मार्कापुरम, 19 अगस्त (पेन पावर): जिला कलेक्टर एम. विजया सुनीथा ने कहा कि जनसमस्याओं का जमीनी स्तर पर समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ लोगों तक बिना देरी के पहुंचाया जाए।

सोमवार को मार्कापुरम कलेक्ट्रेट में आयोजित जन शिकायत समाधान प्रणाली (पीजीआरएस) कार्यक्रम में कलेक्टर ने जनता से 222 शिकायतें प्राप्त कीं। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत की गहन जांच कर निर्धारित समय के भीतर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्राप्त 222 शिकायतों में 170

राजस्व विभाग से संबंधित और 52 अन्य विभागों से संबंधित थीं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार क्षेत्र स्तर पर जांच कर शिकायतों का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर पी. श्रीनिवासुलु, आरडीओ वेंकट शिवरामिरेड्डी, आरडीओ अजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिलाओं को बराबर नहीं मानते कुछ पुरुष : सबा आजाद

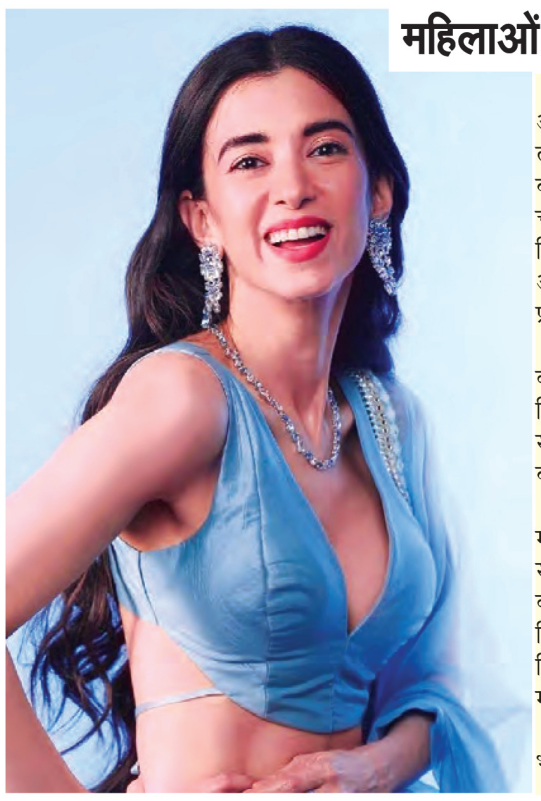

अभिनेत्री, गायिका और वॉयस ओवर आर्टिस्ट सबा आजाद 'दिल कबड्डी' से लेकर'बंदर' जैसी फिल्मों और 'रॉकेट ब्वॉयज' जैसी वैब सीरीज में काम कर चुकी है। उसका मानना है कलाकार को किसी चलन का हिस्सा बनने के बजाय अपने भीतर की रचनात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इस बार चर्चा सिर्फ उसके अभिनय की नहीं, बल्कि महिलाओं की आजादी, रिश्तों में बराबरी और अपनी पेशेवर सोच को लेकर दिए गए उसके बेबाक बयानों की भी हो रही है।

समाज में स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी महिलाओं को लेकर मौजूद सोच पर सबा ने खुलकर अपनी राय रखते हुए कहा है कि भले ही महानगर आधुनिक दिखते हों, लेकिन जमीनी स्तर पर पितृसत्तात्मक सोच अब भी गहराई से मौजूद है।

सबा के अनुसार, महिलाओं को आज भी सम्मान और पहचान हासिल करने के लिए पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उसने कहा कि समाज महिलाओं के हर फैसले का मूल्यांकन करने में देर नहीं लगाता। अगर कोई महिला अपने करियर पर ध्यान देती है तो सवाल उठते हैं, और यदि वह काम न करे, तब भी उसे आलोचना का सामना करना पड़ता है।

रिश्तों में बढ़ते तनाव पर बात करते हुए सबा ने कहा कि समस्या तब पैदा होती है, जब कुछ पुरुष महिलाओं को अपने बराबर स्वीकार नहीं कर पाते।

उसके अनुसार, कई लड़कों की परवरिश ऐसे माहौल में होती है, जहां उन्हें बचपन से ही खुद को महिलाओं से श्रेष्ठ समझना सिखाया जाता है। ऐसे में जब उनका सामना आत्मनिर्भर और मजबूत विचारों वाली महिलाओं से होता है, तो उनका अहं आहत हो जाता है और यही रिश्तों में टकराव की बड़ी वजह बनती है।

एक्टिंग से रोकने के लिए कमरे में बंद कर देती थीं मां : सयानी गुप्ता

यानी गुप्ता उन अभिनेत्रियों में शामिल है, स जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और अलग तरह के किरदारों से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। अपने करियर में उसने भले ही कम फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उसके निभाए हर किरदार ने दर्शकों और समीक्षकों की खूब तारीफ हासिल की है । लीक से हटकर भूमिकाएं चुनने के लिए मशहूर सयानी को इंडस्ट्री की बोल्ड और बेबाक अभिनेत्रियों में गिना जाता है ।

एक्टिंग के लिए छोड़ दी थी कॉर्पोरेट नौकरी

सयानी ने अपनी निजी जिंदगी और एक्टिंग करियर की शुरुआत से जुड़े कई खुलासे करते हुए बताया है कि बचपन से ही उसका सपना अभिनेत्री बनने का था और वह इस फील्ड को करीब से समझना चाहती थी । हालांकि, इस फैसले में उसे मां का साथ नहीं मिला । सयानी ने बताया कि फिल्मों में आने के लिए उसने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दी थी, जिससे उसकी मां काफी नाराज हो गई थी। जब उसने एक्टिंग सीखने के लिए फिल्म एंड टैलीविजन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया, तो मां ने करीब एक महीने तक उससे बात नहीं की ।

सयानी ने फिल्म इंस्टीच्यूट के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, ₹मेरी मां ने मुझसे कहा कि मैं अपनी कलाई काट लूंगी अगर तुम वहां गई । मुझे विश्वास नहीं हो रहा था । मैं बोर हो गई थी। उस एक साल

मैंने पैसे तो बहुत कमाए क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता था लेकिन ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी के लिए नहीं चुना था । ₹ सयानी ने बताया कि मां उसे थिएटर प्रैक्टिस कर नहीं जाने देती थी और कमरे में बंद कर देती थी । हालांकि, समय के साथ मां ने उसके फैसले को समझा और उसके सफर को स्वीकार किया ।

'रकुल प्रीत सिंह' इसलिए बनी 'शूर्पणखा'

अब तक उसे रोमांटिक और आधुनिक किरदारों में देखा गया है, लेकिन शूर्पणखा जैसा जटिल चरित्र उसके अभिनय की नई परीक्षा है। बॉलीवुड में ऐसे कलाकार कम हैं जो अपनी स्टार इमेज से आगे बढ़कर चुनौतीपूर्ण किरदारों को अपनाने का साहस दिखाते हैं। रकुल प्रीत सिंह उन्हीं अभिनेत्रियों में शामिल है, जो अब केवल ग्लैमरस भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायणः पार्ट वन' में शूर्पणखा का किरदार निभाकर रकुल न सिर्फ अपने करियर का सबसे अलग अध्याय लिख रही है, बल्कि दर्शकों की वर्षों पुरानी सोच को भी नई दिशा देना चाहती है ।

फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही रकुल के शूर्पणखा अवतार की चर्चा तेज है। हाल ही में एक प्रशंसक ने उ से कहा कि शूर्पणखा को सदियों से केवल एक घटना के आधार पर याद किया जाता है, जबकि वह रामायण का बेहद जटिल और कहानी की दिशा बदलने वाला पात्र है। इस पत्र का जवाब देते हुए रकुल ने कहा कि एक कलाकार के रूप में उसे ऐसे किरदार सबसे अधिक आकर्षित करते हैं, जो लोगों की बनी-बनाई धारणाओं को चुनौती दें। उसके अनुसार इतिहास ने शूर्पणखा को सिर्फ एक पल में समेट दिया, जबकि उसकी कहानी कहीं अधिक गहरी और बहुआयामी है । उसे उम्मीद है कि फिल्म देखने के बाद दर्शक इस पात्र को नए नजरिए से समझेंगे।

अब सबसे बड़ी प री क्ष ा 'रामायण' रकुल प्रीत के करियर में 'रामायणः पार्ट वन' एक निर्णायक पड़ाव साबित हो सकती है। अब तक उसे रोमांटिक और आधुनिक किरदारों में देखा गया है, लेकिन शूर्पणखा जैसा पौराणिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र उसके अभिनय की नई परीक्षा है ।

यदि वह इस किरदार के ज रि ए दर्शकों की स्थापित धारणाओं को बदलने में सफल रहती है, तो यह न केवल उसके करियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में शामिल होगा, बल्कि साबित करेगा कि एक कलाकार की असली पहचान उसकी जोखिम उठाने की क्षमता और किरदारों के चयन से बनती है।

दीवाली 2026 पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म शूर्पणखा के रोल में रकुल रकुल को भी उतनी ही उम्मीदें हैं, जितनी दर्शकों को । अब देखना दिलचस्प होगा कि पर्दे पर शूर्पणखा का उसका रोल दर्शकों की सोच को कितना बदल पाता है ।

5 लाख रुपए और पहली फिल्म की कहानी

आज बड़ी-बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाली रकुल की अभिनय यात्रा किसी सुनियोजित योजना का परिणाम नहीं थी। उसने खुद स्वीकार किया है कि कॉलेज के दिनों में उसका अभिनय से कोई लेना-देना नहीं था । पोर्टफोलियो बनवाने के कुछ ही दिनों बाद उसे कन्नड़ फिल्म 'गिल्ली' प्रस्ताव मिला। शुरुआत में वह असमंजस में थी, लेकिन जब पता चला कि फिल्म के लिए उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसने तुरंत हामी भर दी। हालांकि, उसने ग्रैजुएशन पूरी करने के बाद ही अभिनय को अपना करियर बनाया ।

दिलचस्प बात यह भी है कि करियर के शुरुआती दौर में उसने पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा दिए, ताकि कॉलेज की पढ़ाई प्रभावित न हो। आज वह मानती है कि बिना किसी गाइडेंस के उसने सैट पर काम करते-करते ही अभिनय की बारीकियां सीखीं।

साऊथ से बॉलीवुड तक का सफर

2009 में कन्नड़ फिल्म 'गिल्ली ' से शुरुआत करने वाली रकुल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद 2013 में तेलुगु फिल्म 'वेंकटाद्री एक्सप्रेस' से दमदार वापसी की। इसके बाद 'लौक्यम', 'नान्नाकु प्रेमाथो', 'सररैनोडु', 'ध्रुव', 'स्पाइडर' और 'अयालान' जैसी फिल्मों से उसने साऊथ सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी फिल्मों में 'यारियां','देदे प्यार दे', 'दे दे प्यार दे 2' और 'मेरे हसबैंड की बीवी' जैसी फिल्मों ने उसे बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों की कतार में ला खड़ा किया।

साऊथ और बॉलीवुड के कामकाज का फर्क

रकुल का अनुभव सिर्फ दो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने दोनों के कार्य- संस्कृति के अंतर को भी करीब से महसूस किया है। उसके अनुसार साऊथ सिनेमा में शूटिंग का समय अधिक व्यवस्थित होता है और अधिकांश काम शाम 6 बजे तक पूरा कर लिया जाता है। वहीं मुंबई में देर रात तक शूटिंग होना सामान्य उसने ब ता या कि हिं दी फिल्म इंडस्ट्री में यूनियन के नियमों के कारण तय समय के बाद अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। शाम 6 बजे के बाद डेढ़ गुना, रात 9 बजे के बाद दोगुना और देररात तक शूटिंग होने पर तीन गुना भुगतान किया जाता है। यही वजह है कि यहां काम करने का ढांचा साऊथ से काफी अलग दिखाई देता है।

मेरे फैन्स मेरी जिंदगी और करियर के कई पड़ावों में मेरे साथ रहे : एलनाज नौरोजी

फिल्म क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली, टैलीविजन और संगीत- तीनों दौरान मिली चुनौतियां, जोखिम और असफलताएं भी उसकी सफलता की कहानी का हिस्सा रही हैं। वह कहती है, यह सफर हमेशा आसान नहीं रहा, लेकिन मैं इसे बदलना नहीं चाहूंगी। मैं खुश हूं कि मुझे हर दिन वह करने का मौका मिलता है, जिसे मैं दिल से पसंद करती हूं।

एलनाज नौरोजी आने वाले समय में भी अलग-अलग तरह की कहानियों का हिस्सा बनना चाहती है। उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है कि उसे अपने जुनून को जीने का मौका मिलता रहे। एलनाज के लिए अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है।

हाल ही में जुबिन नौटियाल के साथ गीत 'हुआ' के जरिए सिंगिंग डेब्यू करने वाली एलनाज अब संगीत की दुनिया भी एक नया सफर शुरू करने जा रही है। 9 जुलाई को उसने अपना जन्मदिन किसी शानदार पार्टी में नहीं, बल्कि अपने आने वाले प्रोजैक्ट के सैट पर काम करते हुए मनाया था। उसके लिए इससे बेहतर जश्न की जगह कोई और नहीं हो सकती थी, क्योंकि कैमरे के सामने रहना और नई कहानियों का हिस्सा बनना ही उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है। एलनाज ने कहा, अभिनय ने मुझे सिर्फ पेशेवर रूप से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ दिया है। हर किरदार मुझे बदलता है और हर प्रोजैक्ट मुझे कुछ नया सिखाता है।

एलनाज का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाता, बल्कि यह उन अनुभवों और यात्राओं को याद करने का मौका बन जाता है, जिन्होंने उसे आज का इंसान बनाया है। उसने कहा कि करियर के

एलनाज ने अपने फैन्स को भी अपनी यात्रा का अहम हिस्सा बताया और कहा कि उनसे मिलने वाले संदेश और शुभकामनाएं उसे खास महसूस कराते हैं। उसने कहा, "मेरे फैन्स मेरी जिंदगी और करियर के कई पड़ावों में मेरे साथ रहे हैं। उनका प्यार और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है । मैं हर उस व्यक्ति की आभारी हूं, जिसने मेरा साथ दिया। योग और संगीत की भी है जिंदगी में अहम जगह

. एलनाज का कहना है कि योग और संगीत ने उसकी पर्सनल और प्रोफैशनल जिंदगी में बदलाव लाने वाली भूमिका निभाई है। उसने कहा, "योग और संगीत, दोनों से मुझे हमेशा एक जैसा सुकून मिला है। दोनों के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा ठहरें, वर्तमान में रहें और अपने अंदर की गहराई से जुड़ें।

'एक आर्टिस्ट के तौर पर, मेरी जिंदगी अक्सर यात्रा, परफॉर्मेंस और लगातार भागदौड़ से भरी रहती है, इसलिए योग मुझे बैलेंस बनाने में मदद करता है, जबकि संगीत मुझे उन भावनाओं को जाहिर करने में मदद करता है, जिन्हें कभी - कभी शब्दों में नहीं कहा जा सकता ।

'यह साल मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मैंने जुबिन नौटियाल के साथ हिन्दी गीतों में गायन की शुरूआत की है। इसके जरिए संगीत की दुनिया में एक रोमांचक नया सफर भी शुरू हो गया है ।

योग की तरह ही, संगीत में भी लोगों को ठीक करने, उनका हौसला बढ़ाने और उन्हें एक साथ लाने की ताकत है । मुझे इस साल दिल्ली में योग डे के खास सैलिब्रेशन का हिस्सा बनने पर गर्व है, और मुझे उम्मीद है कि हर किसी को कोई न कोई ऐसी चीज मिलेगी - चाहे वह योग हो, संगीत हो या कुछ और जिससे उन्हें खुशी, ठहराव और अंदरूनी शांति मिले।

सिनेमा को मानती है बदलाव का माध्यम

एलनाज का मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई दिखाने का एक मजबूत माध्यम भी है।

.. ईरानी मूल की एलनाज ने ईरानी सिनेमा की तारीफ करते हुए कहा कई फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों के जरिए वहां के लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचाई है । उसके अनुसार, ईरानी सिनेमा ने दुनिया को वहां की ज मी नी ह की क त समझने में मदद की है। वह खुद भी फिल्म 'तेहरान ' का हिस्सा रह चुकी है, जिसमें ईरान और इजरायल के बीच तनाव की पृष्ठभूमि दिखाई गई थी ।

मैं ऐसी महिला का किरदार करना चाहती हूं जिसे दर्शक याद रखें : हुमा खुरैशी

मैं ऐसी महिलाओं के किरदार निभाना चाहती हूं, जिनमें कमियां हों, जो वास्तविक लगें और जिन्हें दर्शक लंबे समय तक याद रखें। बॉलीवुड में जब भी अलग और लीक से हटकर किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों का जिक्र होता है, तो हुमा कुरैशी का नाम सबसे पहले सामने आता है । 'महारानी', 'तरला', 'मोनिका, ओ माय डार्लिंग' और अब 'बेबी डू डाई डू' तक हुमा की फिल्मों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि उसने हमेशा अलग और जोखिम भरे किरदारों को चुना है । हुमा कहती है कि उसे कभी भी एक जैसे किरदार दोहराने में दिलचस्पी नहीं रही। उसके अनुसार, अगर कोई रोल उसे थोड़ा डराता है, तो वही उसके लिए सही चुनौती बन जाता।

वह कहती है, "मैं ऐसी महिलाओं के किरदार निभाना चाहती हूं, जिनमें कमियां हों, जो वास्तविक लगें और जिन्हें दर्शक लंबे समय तक याद रखें। मेरे लिए सफलता किसी तय ढांचे में फिट होने का नाम नहीं है, बल्कि हर बार खुद को एक कलाकार के रूप में विकसित करना और दर्शकों के साथ-साथ खुद को भी चौंकाते रहना है।

'बदलापुर' में निभाए अपने बोल्ड किरदार को लेकर किया बड़ा खुलासा

हुमा ने फिल्म 'बदलापुर' में निभाए अपने बोल्ड किरदार को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि सैक्स वर्कर का रोल निभाना उसके लिए आसान नहीं था और वह शुरुआत में काफी डर गई थी । हुमा ने कहा कि यह उसका अब तक का सबसे ट्रिकी और इमोशनली चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि किरदार के साथ एक रेप सीन भी जुड़ा हुआ था, जिसे सही तरीके से दिखाना बहुत मुश्किल था ।

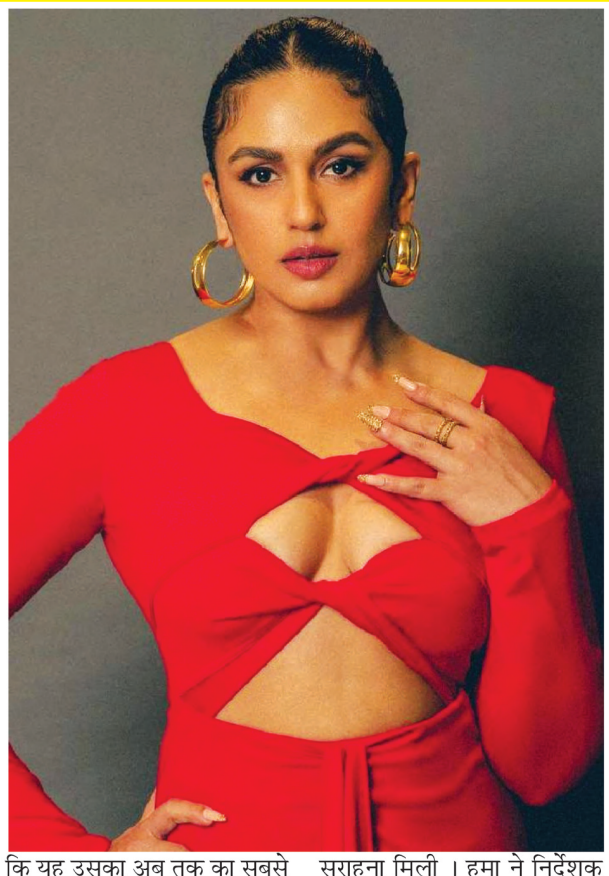

उसका कहना था कि कहानी का असली असर तभी आता है जब दर्शक किरदार के साथ घटना को गलत महसूस करें और उससे जुड़ पाएं। उसने यह भी माना कि उस समय वह पूरी तरह असमंजस और घबराहट में थी। हालांकि, बाद में यह रोल उसके करियर का अहम हिस्सा बन गया और उसे इसके लिए काफी सराहना मिली । हुमा ने निर्देशक श्रीराम राघवन की भी तारीफ की, जिन्होंने उसे यह चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने का मौका दिया।

एक और चुनौतीपूर्ण किरदार

अपने हर नए प्रोजैक्ट के साथ दर्शकों को चौंकाने वाली हुमा हाल ही में फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में भी एक ऐसे किरदार में नजर आई जो उसके लिए एक और चुनौतीपूर्ण रोल रहा । इस फिल्म में वह एक गूंगी-बहरी कॉन्ट्रैक्ट किलर बनी जो छतरी को अपना हथियार बनाकर लोगों की हत्या करती है ।

दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में हुमा ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि अपने भाई साकिब सलीम के साथ इसे प्रोड्यूस भी किया है। उसके अपोजिट इस फिल्म से नए अभिनेता रचित सिंह ने बॉलीवुड में कदम रखे हैं। फिल्म में हुमा का किरदार न बोल सकता है और न सुन सकता है। ऐसे में उसके लिए अभिनय का सबसे बड़ा माध्यम केवल आंखें, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज रहे। इस चुनौती के लिए उसने सुनने और बोलने में असमर्थ लोगों के संवाद करने के तरीके को करीब से समझा। हालांकि, वह नहीं चाहती थी कि उसके किरदार की पहचान केवल उसकी दिव्यांगता तक सीमित रह जाए। उसके लिए 'बेबी' एक ऐसी महिला है, जिसमें डर भी है, कमजोरी भी और जबरदस्त ताकत भी । हुमा स्वीकार करती है कि यह उसके करियर के सबसे कठिन अनुभवों में से एक रहा, लेकिन उतना ही संतोष देने वाला भी।

प्रियंका बहुत कूल है

वहीं हुमा से जब पूछा गया कि अगर 24 घंटे के लिए किसी स्टार का इंस्टाग्राम अकाऊंट इस्तेमाल करने का हुमा ने मौका मिले, तो वह किसे चुनेगी ? पहले तो थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया। जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो उसने हंसते हुए कहा, "मैं बस देखना चाहती हूं कि उनके इंस्टाग्राम अकाऊंट के अंदर क्या चल रहा है। वह बहुत कूल हैं । उसका यह मजाकिया जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

Printed and Published by **GANTYADA APPARAO** on behalf of **GANTYADA APPARAO**, Printed at Sri Sai Ganga Printers and Publishers Flat No: 504, Bharat Towers, 5th Lane, Dwaraka Nagar, Visakhaptanam, Andhra Pradesh-530016, and Published at H.NO: 38-4-216, MAHARANI STREET, MARRIPALEM, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530018, **Editor: GANTYADA APPARAO.** Mobile : 9059465965, **RNI : APHIN/26/A3657**, editorpenpower@gmail.com